

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को पन्द्रह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी। इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी।

कल विश्वकर्मा जयंती है, उस उपलक्ष्य में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैबिनेट ने हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ-प्रोविडेंट फण्ड का जो नियम है उस नियम में अब तक फिफ्टीन थाउजेंट रुपीज की सीलिंग रहा करती थी ये सीलिंग दो हजार चौदह में तय की गयी थी। इसको बढ़कर पच्चीस हजार रुपये पर मंथ सैलरी पर लेकर आ गये।

अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड-एनएसजी के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को कल मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन-आईएमए के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है।

एमएस गोरखपुर में आ गया। गोरखपुर में आज दो मेडिकल कॉलेज, चार विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित हैं। महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकरनगर। इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं में बेहतरीन बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के जंगल नकहा नंबर दो में कल्याण मंडपम का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 40 करोड़ रुपये की लागत वाली 119 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह को सम्बोधित किया।

रक्षा मंत्रालय ने सेना पदक, नौ सेना पदक और वायु सेना पदक-वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए विशेष पहल की है।

रक्षा मंत्रालय ने सेना पदक, नौ सेना पदक और वायु सेना पदक-वीरता पुरस्कार विजेताओं, उनके जीवन साथियों और अविवाहित मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं के माता-पिता के लिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय एसी और एसी चेयर कार में आजीवन ट्रेन यात्रा सुविधाओं को मंजूरी दे दी है। इसके लिए योग्य लाभार्थी भारतीय रेलवे रियायत कार्ड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रमाणीकरण के बाद एक नवंबर दो हजार छब्बीस से आईआरसीटीसी वेब पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग के साथ ई-पास ऑनलाइन जेनरेट किए जाएंगे। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के तहत लेनदेन के साथ-साथ व्यापारियों को दो हजार रुपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल दो हजार रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानि पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट यानि एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। दो हजार रुपये से अधिक के पी-टू-एम लेनदेन पर शून्य दशमलव चार प्रतिशत की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75 हजार रुपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 कल से देशभर में शुरू होगा। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है- 'स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत'। यह विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है।

मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीस सितम्बर तक कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जतायी है। विभाग ने आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है।
